के लिए कौन सी कार्यवाही की गई है और कितनी ऐसी टकसालों का पता लगाया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : चूंकि यह एक ला एंड आर्डर का सवाल था, इसलिए इस सम्बन्ध में स्टेट गवर्नमेंट्स से लिखा-पढ़ी हुई और उन की कार्यवाही से बहुत जगहों में काफी लोगों को पकड़ा गया है और जो उचित कार्यवाही होती है, वह की गई है।

श्री भक्त दर्शन : क्या सरकार के ध्यान में ये बात आई है कि जिस तरह चिराग तले अन्धेरा होता है, उसी तरह केन्द्रीय सरकार के बिल्कुल नीचे स्वयं दिल्ली में पीली दुअन्नियों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिस के परिणामस्वरूप जनता को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : दिल्ली सरकार ने एक विज्ञप्ति निकाली है, जिस में बताया गया है कि पीली दुअन्निया चलनसार हैं और जिनकी दुअन्निया नहीं ली जाती हैं, मैं उन्हें स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक के आफ़िसिज़ और एजेन्सीज़ में बदलवा सकते हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या मन्त्री जी ने कभी रेलवे, डाकखाने और सरकार के दूसरे दफ्तरों में जा कर देखा है कि पीली दुअन्नियां स्वीकार की जा रही हैं ?

श्री ब० रा० भगत : ये सारी सूचनायें मालूम की गई हैं।

डा० रा० सुभग सिंह : भाग (ख) के उत्तर में बताया गया है—नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में किस ट्रेज़री का अनुभव है, जिसके आधार पर यह जवाब दिया गया है। क्या साधारण आदमी को ट्रेज़र में जा कर पीली दुअन्नियां बदलवाने का अधिकार है ?

श्री ब० रा० भगत : आम तौर से एक दुअन्नी के लिये इतनी कठिनाई नहीं होती, लेकिन अगर कठिनाई हो, तो उस को रिजर्व बैंक की एजेन्सी से या स्टेट बैंक में बदलवाया जा सकता है।

Mr. Speaker: The Minister may issue a statement and try to relieve the difficulties by explaining the position to the general public.

Shri Radhelal Vyas: It is not accepted even in the Notice Office and in the Post Offices.

Shri M. L. Dwivedi: May I put one small question? This is a very important matter.

Mr. Speaker: Two-anna pieces are not very important.

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): We have already issued a press note sometime back, and I am perfectly prepared again to issue a press note on the lines indicated by the Chair.

Mr. Speaker: And, give due instructions also

Shri Sadhan Gupta: Even in the Delhi State Transport buses they are not accepted.

Mr. Speaker: Instructions may be issued saying that these must be accepted

Raja Mahendra Pratap: Some people are selling two-anna pieces for one anna It is a good business.

Mr. Speaker: I have not been able to provide any particular rule, so far as the hon. Member is concerned.

पंजाब में हिन्दी आन्दोलन

*५८० श्री विभूति मिश्र : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में हिन्दी भाषा के सम्बन्ध में अभी जो सत्याग्रह चल रहा है उसके बारे में कुछ शिष्टमण्डलों ने उनसे तथा शिक्षा मंत्री से भेंट की है, और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) कुछ व्यक्ति गृह मंत्री तथा शिक्षा मंत्री से मिले हैं।

(ख) उनको पंजाब की भाषाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रादेशिक फार्मूले की वास्तविकता समझाई गई और सलाह दी गई कि वे आन्दोलन समाप्त कर दें।

Some Hon. Members: We want the answer in English also.

Shri Datar: (a) Some individuals have met the Minister of Home Affairs and the Minister of Education.

(b) The correct implications of the *regional formula in so far as it relates* to arrangements regarding languages in Punjab were explained to them and they were advised to discontinue the movement.

श्री विभूति मिश्र : पंजाब का झगड़ा बहुत बढ़ गया है। हमारे गृह मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं। क्या वह इस झगड़े का कोई एक सक्रिय निराकरण का उपाय उन लोगों को बता रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि झगड़ा खत्म हो।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या गृह मंत्री जी उनको कोई कारगर बात बतायेंगे जिससे झगड़ा खत्म हो जाए ?

पंडित गो० ब० पन्त : उनको बहुत कार मद बात बतलाई गई है कि जो रीजनल फार्मूला है और उसमें जो बात तय की गई है वह बहुत ध्यानपूर्वक तथा सब पहलुओं को सोच कर तय की गई है और उसे उन्हें भी मान लेना चाहिए और इस झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिये।

Shri Ajit Singh: May I know what is the type of satyagraha launched by the Hindi Raksha Samiti, whether it is peaceful or unlawful?

Pandit G. B. Pant: It is for the local Government to decide what is the exact character of the satyagraha.

Shri Ajit Singh: May I know whether it is a fact that some of the Ministers and the Secretaries were held up outside the Secretariat by the satyagrahis?

Pandit G. B. Pant: May be so.

चौ० प्र० सि० दौलता : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब को यह बात मालूम है कि हरियाना में इस हिन्दी के नाम से इस कद्र गन्दा प्रचार किया जा रहा है कि वहां फिरकावाराना फसादात फिर जल्दी शुरू हो जाने का खतरा है ? क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब को यह भी मालूम है कि इस के तह में सभी वे कांग्रेसी मिनिस्टर हैं जिनको कि इस बार कांग्रेस मिनिस्टरी में नहीं लिया गया है तथा उनके अखबार, उनके बाप, उनके सुसर सभी हरियाना के इलाके में इतना जहरीला प्रचार कर रहे हैं कि फिरकावाराना फसादात शुरू होने का खतरा है ?

पंडित गो० ब० पन्त : आपके जो ख्यालात हैं या आपको जो कुछ मालूम है वे वहां रहते हुए ज्यादा सही हो सकते हैं बिलमुकाबिल मेरे किसी बात को जानने के।

Shri Tyagi: I protest, Sir. I am a Minister who has not been taken in the Cabinet.

Shri Hem Barua: In view of the Sachar Formula which provides for every Punjabi, irrespective of caste, community and religious affiliation, learning Hindi, what is there for the Samiti, which has started the agitation, to save?

Pandit G. B. Pant: Perhaps they did not understand the implications of the Regional Formula.

Raja Mahendra Pratap: Is this not a caste struggle in Punjab?

An Hon. Member: It is a class struggle.

पंडित बृज नारायण "ब्रजेश" : पंजाब में जो यह झगड़ा चल रहा है, उसको क्या हमारी सरकार एक राउंड टेबल कांफ्रेंस बुलाकर सुलझा नहीं सकती या दोनों को एक साथ बिठाकर हमको तय नहीं कर सकती ? सरकार इस बात को जानती ही है कि वहां एक विषम स्थिति पैदा हो गई है और लड़ाई का इस तरह से चलते रहना ठीक नहीं होगा। दोनों को बुलाकर के, क्या सरकार उनमें समझौता करानें का प्रयत्न नहीं कर सकती या कर नहीं रही है ?

Mr. Speaker: It is a suggestion for action.

पंडित गो० ब० पन्त : सरकार को इस का बड़ा दुःख है पर सरकार चाहती है कि दोनों मिल जुल कर रहें और आपस में झगड़ा न करें ।

Raja Mahendra Pratap: My question is not answered. I asked, 'Is this not a class struggle in Punjab?'

Mr. Speaker: Next question.

Pandit G. B. Pant: Caste questions have to be considered outside the House.

Central Sales Tax Act

*581. **Shri Heda:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the reasons for postponing further the date of enforcement of section 15 of the Central Sales Tax Act 1956; and

(b) the names of the States which desired further postponement.

The Deputy Minister of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) Section 15 of the Central Sales Tax Act, 1956 was amended in May, 1957 session of the Parliament and it was necessary to bring the existing provisions of the various State Sales Tax Acts to accord with the amended Section, before it could be enforced. The date of enforcement of the said Section was, therefore, postponed to 1st October, 1957 in order to enable the State Governments to amend their sales tax laws, where necessary;

(b) Bombay, Orissa, Madras and Mysore.

Shri Heda: May I know what will happen in the contingency of all the State Governments not being able to amend their Acts by the 1st of October?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): If that hypothetical contingency eventuates, we will have to take some action then to see whether we could not meet them more than half way.

Shri Heda: May I know what reasons the four States have given for further postponement?

Shri T. T. Krishnamachari: I suppose their legislative convenience does not permit their making the necessary amendments.

Shri Ranga: How is it that when our merchants go to the local officers, they are not given proper guidance as to how much is to be collected, what to pay and where to pay? There are so many complaints about forms not being made available. These were also sent to the Ministry. I am referring to Andhra Pradesh.

Shri T. T. Krishnamachari: So far as the Central Government is concerned, it has no jurisdiction over Andhra Pradesh. The Central Sales Tax, though it is called the Central Sales Tax, is collected by the State Governments and the beneficiaries are the State Governments. Therefore, the matter is entirely within the purview of the State Governments, and the Central Government cannot give any information in this regard. I know that certain States have taken up the matter with alacrity, particularly Bombay. They have printed all the forms necessary and every dealer has been registered and things are moving. But in some States, they are not moving quite so fast. All we can do when we get to know about it is to write to the State Governments asking them to act. We have no authority at all to compel action.